

उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राथमिक शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों में जागरूकता का विश्लेषण

मुकेश मेहरा

राजनीति विज्ञान विभाग, पी.जी. कॉलेज रानीखेत (उत्तराखंड)

जया नथानी, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, रानीखेत (उत्तराखंड)

सारांश :- इस रिसर्च पेपर का लक्ष्य यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा को लेकर कितनी जागरूकता रखते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में जहां व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर पर आ चुका है जहां उसकी शिक्षा क स्तर अत्यधिक उच्च है, अब यहाँ यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वह प्राथमिक शिक्षा को लेकर कितना जागरूक है तथा प्राथमिक स्तर पर चुनौतियों से निपटने के लिए वह अपने स्तर पर क्या कार्य कर सकता है और ऐसे क्या सुझाव दे सकता है जिससे प्राथमिक स्तर की शिक्षा को और बेहतर किया जा सके। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राथमिक शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों में जागरूकता का विश्लेषण करने हेतु दो उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों को केंद्र में रखकर छात्रों और छात्राओं में प्राथमिक शिक्षा को लेकर जागरूकता का पता लगाया गया तथा उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा में सुधार को लेकर दिए गए सुझावों का अध्ययन किया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा कि जागरूकता को लेकर प्रतिशत उच्च है। अतः उनसे अपेक्षित है कि वह अपने क्षेत्र के जहां तक संभव हो प्रत्येक बच्चे को जागरूक करने का प्रयास करे।

की वडर्स :- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2001, प्राथमिक शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के जागरूकता का स्तर ज्ञात करना तथा उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा सुधार को लेकर दिए गये सुझावों का अध्ययन करना, उच्च शिक्षण संस्थानों में (20 छात्र, 20 छात्राएँ)

प्रस्तावना :- भारत में शिक्षा की स्थिति जब भारत को स्वतंत्र हुए सत्तर वर्षों से अधिक हो चुके हैं अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंची जहां विकसित राष्ट्रों में पहुंची है। भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित अवस्था में पहुँचने के लिए शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। बिना बेहतर शिक्षा के कोई भी राष्ट्र विकसित अवस्था में नहीं पहुँच सकता यह एक सर्वमान्य तथ्य है। भारत में शिक्षा तीन स्तरों में विभाजित है जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भले ही कुछ मात्रा में विकास दिखता हो हालांकि यह गावों कस्बों में हाशिये पर ही है परन्तु प्राथमिक स्तर की शिक्षा की स्थिति अति संवेदनशील है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा को लेकर कई सुधार किये गए जैसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2001 जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 86 वे संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21(क) में रखा गया। पंचवर्षीय योजना के तहत ब्लैकबोर्ड योजना, वर्ष 2000 में सर्व शिक्षा अभियान तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया गया। शिक्षा को अच्छी स्थिति में लाने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च तीनों स्तरों पर बेहतर कार्य करने होंगे और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्तर जो व्यक्ति के विकास में एक नींव का कार्य करती है।

उद्देश्य :- शोध अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत :-

(1)-प्रयोग में लाये गए दो उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में प्राथमिक शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों में जागरूकता का विश्लेषण

(2)-छात्रों तथा छात्राओं के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए दिए गए सुझावों का अध्ययन करना

क्रिया विधि :- अध्ययन का क्षेत्र :- नैनीताल जनपद के अंतर्गत आने वाले दो उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान डी०एस०बी ० परिसर नैनीताल तथा एम०बी० पी०जी० कॉलेज हल्द्वानी में आने वाले छात्र तथा छात्राओं को चुना है।

न्यादर्श अथवा प्रतिदर्श :- नैनीताल जनपद के एम०बी० पी०जी० कॉलेज हल्द्वानी तथा डी०एस०बी ० परिसर नैनीताल में विद्यार्थियों के चयन हेतु न्यादर्श की यादृच्छिक/देव निर्देशन विधि का प्रयोग किया गया है।

डाटा संग्रहण :- उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राथमिक शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों में जागरूकता के विश्लेषण हेतु (20-20) छात्र- छात्राओं के लिए अनुसूची मेथड के तहत प्रश्नों को तैयार किया गया तथा उन पर प्रसारित किया गया और प्रश्नों का सावधानी पूर्वक जवाब लिया गया तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों का भी अध्ययन किया गया।

सांख्यिकी विश्लेषण :- संग्रहीत प्रदत्तों का सांख्यिकी विश्लेषण प्रतिशत आकलन द्वारा किया गया। पद संख्या एक से दस तक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम व द्वितीय उच्च शिक्षण संस्थानों हेतु निम्न सारणी प्रस्तुत की गयी है :-

क्रम संख्या	20 छात्रों द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर			20 छात्राओं द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर		
	सही	गलत	कोई उत्तर नहीं	सही	गलत	कोई उत्तर नहीं
1	18	1	1	19	1	0
2	20	0	0	20	0	0
3	20	0	0	20	0	0
4	18	1	1	19	1	0
5	13	7	0	11	9	0
6	17	3	0	16	3	1
7	12	6	2	10	10	0
8	15	5	0	15	4	1
9	20	0	0	20	0	0
10	9	8	3	10	7	3

क्रम संख्या	20 छात्रों द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर			20 छात्राओ द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर		
	सही	गलत	कोई उत्तर नहीं	सही	गलत	कोई उत्तर नहीं
1	19	1	0	19	1	0
2	20	0	0	19	1	0
3	20	0	0	20	0	0
4	17	3	0	19	1	0
5	15	5	0	14	6	0
6	17	2	1	17	1	2
7	13	7	0	14	6	0
8	16	4	0	15	5	0
9	20	0	0	20	0	0
10	10	10	0	12	8	0

परिणाम तथा निष्कर्ष :- दोनों उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा को लेकर कुछ प्रश्नों का संकलन किया गया तथा प्रारंभिक स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में जागरूकता का प्रतिशत ज्ञात किया गया जो उच्च स्तर पर रहा परन्तु नवीन आकड़ों के प्रश्नों में यह प्रतिशत मध्य स्थिति में रहा। क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को लेकर जागरूकता का स्तर उच्च है इसलिए उनसे अपेक्षित है कि वह अपने स्तर पर शिक्षा को लेकर कार्य करे तथा जहाँ तक संभव हो प्रत्येक बच्चे को जागरूक करने का प्रयास करे।

सुझाव :- (1)- हर एक व्यक्ति जो उच्च शिक्षा से सम्बंधित है अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा को लेकर जागरूक कर सकता है।

(2)- तकनीक के माध्यम से गूगलमीट पर सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के विषय में जागरूकता प्रदान करना |

(3)- एन सी सी तथा एन एस एस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को शिक्षा के महत्व की बारीकियों को समझाना तथा उससे सम्बंधित कोई नाट्य प्रस्तुत करके शिक्षा की आवश्यकताओं को समझाना।

(4)- प्राथमिक स्तर के अध्यापको द्वारा अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाकर सभी को सामान रूप से शिक्षित करना साथ ही शिक्षा के महत्व को समझाना।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :- शिक्षा का मौलिक अधिकार पी०पी०राव,भारतीय विधि संस्थान का जर्नल 50(4) 585-592,2008

उत्तराखंड,भारत में शिक्षा के अधिकार कि संभावनाएँ,चुनौतियाँ और उपलब्धियाँ अनामिका चौहान,अनीता सती, शैक्षिक विज्ञान के अनुसंधान जर्नल,ई -आई एस एस एन 2321,0508,2016

मानव अधिकार के नार्डिक जर्नल,खंड 40,2022 -अंक-1 अब समय आ गया है कि शिक्षा के अधिकार का विस्तार किया जाए

शिक्षा और लैंगिक समानता यूनेस्को(25-04-2013)

समकालीन भारत एवं शिक्षा शिक्षक शिक्षा विभाग,शिक्षा शास्त्र विद्याशाला उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी राईट टू एजुकेशन एक्ट,2010

www.uk.gov.in

www.education.gov.in

